● वर्ष-14 ● अंक-10 ● अगस्त- 2026 R.N.I. No. MPHIN/2012/52196 मूल्य-25/-

# संदर्भ दर्पण

## नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर - मुख्यमंत्री साय

संदर्भ दर्पण, सितम्बर 2016, आरएनआई एमपीएचआईएन/2012/52196 डाक पंजीयन संख्या म.प्र./भोपाल/4-411/2016-18

# क्या आप अपना स्वयं का

# उद्योग/व्यवसाय/ स्वरोजगार/ एनजीओ

# प्रारंभ करना चाहते हैं

**संदर्भ शिक्षण प्रशिक्षण वेलफेयर समिति (सेटवेल) के स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में अपना नाम पंजीबद्ध कराएं समिति के द्वारा आपके ही क्षेत्र में निम्नानुसार विषयों पर सशुल्क प्रशिक्षण की योजना बनाई जा रही है :**

1. उद्योग/व्यवसाय/ स्वरोजगार/ एनजीओ के सहायतार्थ संचालित प्रमुख योजनाएं
2. स्थानीय निकायों में पंजीकरण के नियम एवं की प्रक्रिया
3. उद्योग आधार नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया
4. कंपनी/फर्म/एनजीओ/सहकारी समिति बनाने हेतु आवश्यक नियम एवं प्रक्रियाएं
5. प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाने की प्रकिया
6. बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रकिया
7. उद्योग स्थापना हेतु मशीनें कहां से खरीदें

**कृपया निम्नानुसार जानकारियों के साथ अपना पता लिखा एवं 5 रू. का डाक टिकट लगा लिफाफा हमारे पते पर प्रेषित करें :**

1. नाम
2. पता
3. ई-मेल
4. मोबाइल/फोन नंबर
5. आयु/जन्मतिथि
6. शिक्षा
7. वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं
8. भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं
9. प्रशिक्षण हेतु आपकी रूचि का क्षेत्र

**कृपया अपना पत्र निम्नानुसार पते पर प्रेषित करें :**

गर्ल्स होली क्रॉस स्कूल के पास मंगल डेरी वाली गली पेंशन बाड़ा
रायपुर छत्तीसगढ़ मोबाइल नंबर 913 1 79 181 5

स्वामी श्रीमती वंदना दुबे, प्रकाशक श्रीमती वंदना दुबे, मुद्रक श्री अजय वैद्य द्वारा पवन प्रिंटर्स, कुश कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं एल.आई.जी.-15, फेस-1, कान्हा कुंज, कोलार रोड-462 042 मध्यप्रदेश से प्रकाशित संपादक श्रीमती वंदना दुबे

● वर्ष 14 ● अंक 10, अगस्त 2026

# संदर्भ दर्पण

**संपादक**
**वंदना दुबे**

**कार्यकारी संपादक**
रामप्रसाद
शिवप्रसाद

**उप संपादक**
आदर्श दीक्षित

**कार्यालय**
**उत्तर प्रदेश**

**प्रयागराज-** गजल एडवर्टाइजर, बी-654/2 जी.टी. बी. नगर, प्रयागराज (इलाहाबाद)

**लखनऊ -** श्री नरेंद्र प्रसाद दुबे, मुनेश्वरम, आलम नगर क्रॉसिंग, नए रेलवे पंप हाउस के सामने, लखनऊ - 226017

**छत्तीसगढ़**
रायपुर - द्वारा श्री रामप्रसाद दुबे, होलीक्रॉस स्कूल के पास, पेंशन बाड़ा, रायपुर - 492 001

**मध्यप्रदेश**
भोपाल- एल.आई.जी.-15, फेस-1, कान्हा कुंज, कोलार रोड, भोपाल- 462 042 मोबाइल -8224057288

**स्वामी श्रीमती वंदना दुबे, प्रकाशक श्रीमती वंदना दुबे,** मुद्रक श्री अजय वैद्य द्वारा पवन प्रिंटर्स, कुश कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं एल.आई.जी-15, फेस-1, कान्हा कुंज, कोलार रोड-462 042 मध्यप्रदेश से प्रकाशित

**संपादक-श्रीमती वंदना दुबे**

## संपादकीय

# यूपीआई और आम आदमी

भारत में यूनिफाइड पेमैंट्स इंटरफेस यानि यूपीआई आधिकारिक तौर 11 अप्रैल, 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा लांच किया गया। अब यूपीआई को एक दशक बीत चुका है। शुरूआत में लोग इसे अपनाने में हिचक रहे थे लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इस सिस्टम को समझा और अपनाया। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो यूपीआई पेमेंट सबसे आसान विकल्प बन गया। महामारी के दौरान लोगों ने रोजमर्रा की वस्तुएं यूपीआई लेन-देन से ही खरीदी।

आज यूपीआई आम आदमी की जरूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। युवा पीढ़ी तो अपने वॉलेट में नकदी रखना ही नहीं चाहते। सब्जी खरीदनी हो, घर में खाना मंगाना हो, छोटी-छोटी चीजों की खरीदारी से लेकर ऑनलाइन शोपिंग तक यूपीआई लोकप्रिय हो चुका है। अब तो यूपीआई से लेन-देन विदेशों में भी सुलभ हो चुका है। डिजिटल पेमेंट घर-घर पहुंचाने में सरकार का भी बड़ा योगदान रहा। मोदी सरकार ने 2020 में यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर को शून्य कर दिया था। जिसके चलते छोटे-बड़े दुकानदारों के ?लिए यूपीआई बिल्कुल मुफ्त बन गया था।

लोकसभा ने गुरुवार को कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। इससे केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के कौन से माध्यम निःशुल्क रहेंगे और किन पर शुल्क लागू हो सकते हैं। हालांकि विधेयक में किसी शुल्क, दर या समय सीमा का उल्लेख नहीं है, फिर भी यह शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए कानूनी लचीलापन प्रदान करता है और संभावित रूप से कुछ एकीकृत भगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन पर एमडीआर लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

विधेयक के पारित होने के बाद कई तरह की अफवाहें फैल गई कि सरकार आम आदमी पर यूपीआई सरचार्ज लगाएगी। आम आदमी को डर यह है कि अगर यूपीआई पर सरचार्ज लगा तो फिर इसका फायदा ही क्या है। विधेयक को लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी सामने आने लगी और इसके साथ अमेरिकी एंगल भी जुड़ गया। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पर सरचार्ज पहले की तरह मुफ्त रहेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने या छोटे दुकानदारों को भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह केवल बड़े व्यापारियों और स्टोरों के लेन-देन पर लगेगा। एक पंक्ति में कहें तो एमडीआर व्यापारी पर लगेगा। आम ग्राहकों का इससे लेना-देना नहीं है। यह चार्ज सिर्फ एक करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए लेन-देन और 2000 से ज्यादा वेल्यू वाले लेन-देन पर ही लगाया जा सकता है। आम आदमी को आशंका है कि बड़े मर्चेंट?अंततः यह खर्च उपभोक्ता पर ही डाल देंगे लेकिन सरकार के स्पष्टीकरण के बाद आम उपभोक्ताओं का भ्रम दूर हो जाना चाहिए। व्यापारियों पर सरचार्ज बढ़ाने को लेकर सरकार का तर्क है कि एमडीआर लागू होने से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को नये निवेश के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। क्योंकि बैंक और फिनटेक कंपनियों को करोड़ों यूपीआई ट्रांजेक्शन संभालने के लिए सर्वर और साइबर सुरक्षा पर बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है। एमडीआर जीरो होने के कारण इन कंपनियों और बैंकों का बिजनेस मॉडल प्रभावित हुआ है जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नया निवेश करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए एमडीआर से होने वाली आय का मुख्य उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को मजबूत बनाना है।

बैंक भुगतान सेवा प्रदाता, भुगतान एग्रीगेटर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बुनियादी ढांचे के रखरखाव, उन्नियन और सुरक्षा का खर्च वहन करते रहते हैं। विधेयक की आलोचना के एक पहलू विदेशी एंगल के पीछे जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की 2026 नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में भारत के यूपीआई और रूपे फ्रेमवर्क के साथ-साथ ब्राजील के पेमेंट सिस्टम पिक्स की भी आलोचना की गई है। अमेरिका का तर्क है कि ऐसे घरेलू डिजिटल भुगतान सिस्टम विदेशी भुगतान कंपनियों को बराबरी का अवसर नहीं देते। हालांकि यूएसटीआर के आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि भारत के यूपीआई मार्केट शेयर में अमेरिकी कंपनियां फोन-पे और गूगल पे का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। जीरो-एमडीआर नीति के कारण इन दिग्गज टेक कंपनियों को भारत में खरबों रुपये के यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और सेफ्टी पर भारी लागत उठानी पड़ रही थी, जबकि राजस्व शून्य था। एमडीआर लागू होने हर साल अरबों रुपये की सीधी कमाई शुरू हो सकती है।

इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड भी लंबे समय से भारत सरकार की जीरो-एमडीआर नीति पर चिंता जताते रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर एमडीआर होने के कारण अधिकतर व्यापारी मुफ्त यूपीआई को प्राथमिकता देते हैं। यूपीआई पर एमडीआर लागू होने से डिजिटल भुगतानों के बीच का यह अंतर कम होगा, वीजा और मास्टर कार्ड का कारोबार बढ़ सकता है, यानी यूपीआई पर एमडीआर लगने से मर्चेंट कार्ड पेमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। विधेयक पारित होने के बाद आर्थिक जगत में यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था मुफ्त में अनिश्चितकाल तक संचालित हो सकती है। दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक यूपीआई से करोड़ों रुपए के लगभग 66 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं और यह डिजिटल भारत की रीढ़ बन गया है। सरकार को यह देखना है कि आम उपभोक्ता किसी भी तरह से प्रभावित न हो और साथ ही इसकी व्यवस्था करनी है कि यूपीआई को बरकरार रखने के लिए उस पर होने वाला खर्च भी हासिल हो जाए।

# आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ - महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय

**डॉ. दानेश्वरी संभाकर, उप संचालक**

किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता से होती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार सशक्त होता है, समाज प्रगतिशील बनता है और विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सुशासन का प्रमुख आधार बनाया है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित योजनाएं आज लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल महतारी वंदन योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ कर रही है। इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में आंगनबाड़ी संचालन हेतु 800 करोड़ रुपये, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये तथा कुपोषण मुक्ति एवं पोषण योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी सदन स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 368 महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 137 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2026-27 में 250 नए महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 34 सखी वन-स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं। यहां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 के समन्वय से त्वरित सहायता व्यवस्था भी प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटरों के संचालन के लिए डिजिटल एसओपी लागू की है। महिलाओं की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण कर रही है, जहां महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा तथा लखपति दीदी भ्रमण योजना के माध्यम से सफल उद्यमियों को देश-विदेश के अध्ययन भ्रमण का अवसर मिलेगा।

बिहान मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 2.92 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनसे 31.65 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री के तीन करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 10 लाख 43 हजार से अधिक लखपति दीदी तैयार की हैं। रेडी-टू-ईट निर्माण, कृषि आधारित उद्यम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों ने ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। महिला निर्माण श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 7,900 रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 24 हजार से अधिक बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है। प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 42,878 महिला समूहों को 129.46 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना जमानत 25 हजार रुपये तक का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 38 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सुशिक्षा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार 139 छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। शुचिता योजना के माध्यम से 2 हजार विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं तथा लाखों किशोरियों को मासिक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला समूहों के उत्पाद आज वैश्विक पहचान भी बना रहे हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित जशप्योर ब्रांड ÷वोकल फॉर लोकल÷ अभियान का सफल उदाहरण बन चुका है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। वहीं सखी साड़ी-मिलेट कैफे जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान बन चुका है। आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, स्वरोजगार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयास महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाएं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। यही बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ को सुशासन से समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर कर रही है।

# ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से बदलेगा छत्तीसगढ़ का औद्योगिक परिदृश्य

## निवेशकों का बढ़ेगा विश्वास, एमएसएमई को मिलेगा संबल, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर

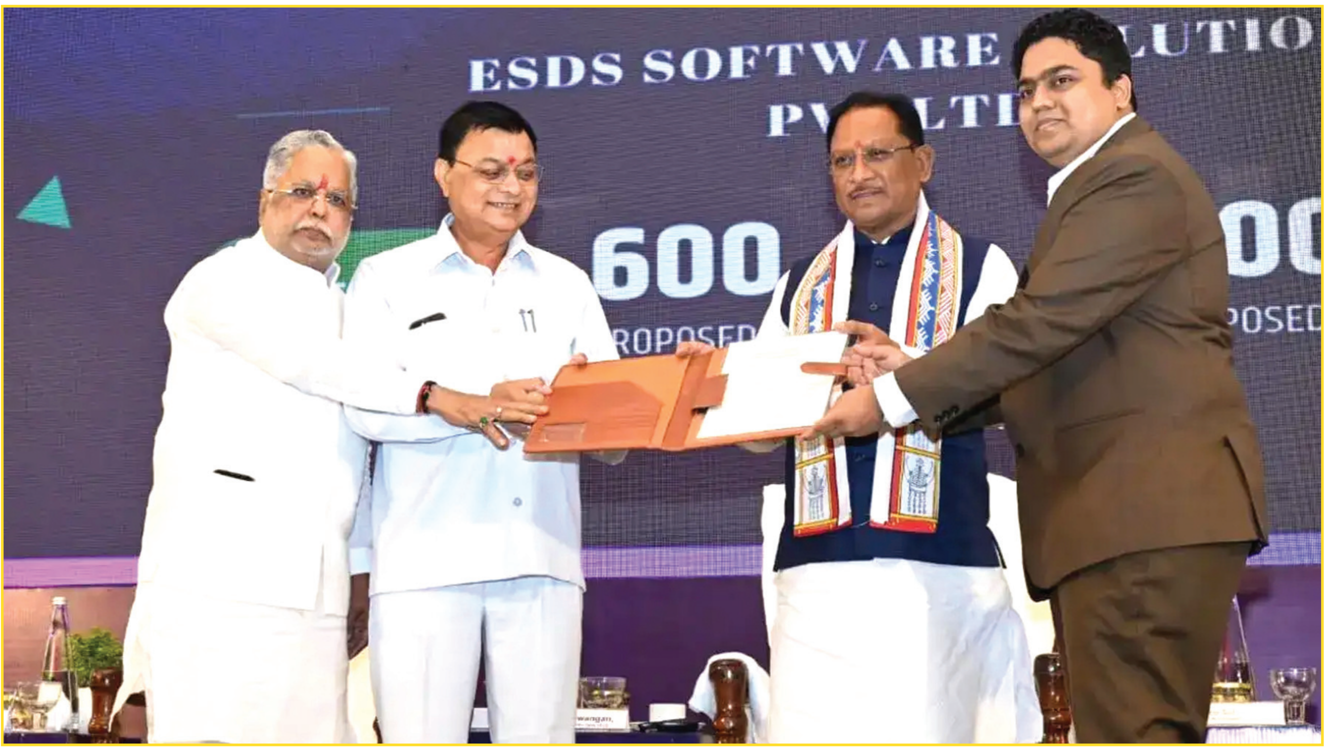


छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026' लागू किया है। सरकार का दावा है कि यह कानून उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू किए गए इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों को समयबद्ध अनुमति, पारदर्शी प्रशासन और अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं से राहत देना है। इसका लाभ बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमियों को भी मिलने की उम्मीद है।

### जोखिम के आधार पर मिलेगी अनुमति

अधिनियम की प्रमुख विशेषता रिस्क-बेस्ड परमिशन सिस्टम

है। इसके तहत उद्योगों को उनके आकार और गतिविधियों के आधार पर जोखिम श्रेणियों में रखा जाएगा। कम जोखिम वाले उद्योगों को सरल और त्वरित स्वीकृति मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में आवश्यक तकनीकी परीक्षण और निरीक्षण जारी रहेंगे।

## सेल्फ सर्टिफिकेशन और डीम्ड अप्रूवल

नई व्यवस्था में ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। कई मामलों में लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या अधिकृत विशेषज्ञों के प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही, पात्र मामलों में निर्धारित समय-सीमा में विभागीय निर्णय नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था लागू होगी। हर वर्ष लाइसेंस और अनुमति के नवीनीकरण की बाध्यता खत्म किए जाने से उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे समय और लागत की बचत होगी तथा कारोबारी अपना ध्यान उत्पादन और व्यवसाय के विस्तार पर केंद्रित कर सकेंगे।

## 15 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ

सरकार के अनुसार प्रदेश के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस व्यवस्था का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। जल प्रदाय की अनुमति, भवन अनुमति और फर्म अथवा सोसायटी पंजीयन जैसी प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है। वर्तमान में राज्य शासन के 8 विभागों की 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली में शामिल किया गया है। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में अन्य विभागों और सेवाओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकेगा।

## निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर के भंडार के साथ राज्य में बिजली, सड़क और रेल संपर्क की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सरल और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था जुड़ने से राज्य को निवेश के लिए और आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है।

नई व्यवस्था से निवेश बढ़ने पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

## तीन स्तरों पर होगी निगरानी

अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद इसकी निगरानी करेगी।

सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें उद्योगों को अनुमति लेने के लिए अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अधिनियम छत्तीसगढ़ में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है।

# मुख्यमंत्री साय ने हाथ में तिरंगा थामकर किया भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

हाथों में लहराता तिरंगा, भारत माता के जयघोष, देशभक्ति के गीत और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हजारों नागरिकों का उत्साह - राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई।

बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थामा गया लगभग एक किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता के जयघोष ने पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्रप्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री साय भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। इस दौरान नागरिकों में मुख्यमंत्री के साथ चलने और राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। यह केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे में देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तिरंगा लहराता है तो प्रत्येक भारतीय के मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जागृत होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का साक्षी है। तिरंगा हमें अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान आज एक व्यापक जनअभियान का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान ने तिरंगे को घर-घर तक पहुंचाने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में पूरे सम्मान और गौरव के साथ तिरंगा फहराने तथा तिरंगा यात्राओं से जुड़कर राष्ट्रीय एकता के इस उत्सव को और भव्य बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में गर्व और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, वह स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान जुड़ा हुआ है। देश के असंख्य वीर सपूतों ने मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर क्षेत्र और समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया। किसी ने अपना जीवन समर्पित किया, किसी ने अपना घर-परिवार छोड़ा और अनेक वीरों ने मातृभूमि के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन बलिदानों के कारण ही आज हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के गौरव का अनुभव कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि की नई पीढ़ी स्वतंत्र भारत में जन्मी और आगे बढ़ रही है। इसलिए उसे यह जानना आवश्यक है कि आजादी कितनी अनमोल है और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवगाथाओं से परिचित होकर ही नई पीढ़ी स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझ सकेगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें उन सभी ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता की इस गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इससे युवाओं के भीतर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समर्पण, सेवा और 'राष्ट्र प्रथम' का भाव और अधिक मजबूत होगा।

# छत्तीसगढ़ का लोक - पर्व :

# हरेली तिहार

छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लोक-त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें प्रकृति, कृषि और जीव-जंतुओं के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। इन्हीं त्योहारों में सबसे पहला और प्रमुख त्यौहार है – हरेली तिहार। सावन माह की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) को मनाया जाने वाला यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन, कृषि परंपरा और पर्यावरण-प्रेम का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उसकी प्रकृति नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएँ भी हैं।

छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में पर्व और त्यौहारों की बहुलता है। प्रत्येक माह कोई न कोई त्यौहार यहाँ लोक मानस को अपने रंग में रंग लेता है। ये त्यौहार जहॉ लोक जीवन में हंसी-खुशी के अवसर उपलब्ध कराती हैं, वहीं खेल और मनोरंजन के अनुकूल साबित होते हैं। प्रकति का यह हरापन छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में भी पूरी समाहित है। हरेली, भोजली, जँवारा हो या बसंत पंचमी सभी पर्वों में प्रकृति का मनोरम और इसका अप्रतिम सौंदर्य झलकता है। इस रूप-सौंदर्य में जीवन की चारों अवस्थाओं का उल्लास और उत्साह विविध रंगों में बिखरा हुआ है। शायद 'हरेली' का हरापन हमारी परंपराओं में हमारे संस्कारों में और हमारे लोक जीवन में प्राकृतिक हरीतिमा का ज्यादा एहसास कराता है। हरेली का यह हरापन सबके जीवन में बिखरे और निखरे यही कामना है। यह भी कामना है कि भौतिकता की चकाचौंध से परे हमारी खेल परंपराएँ जीवित रहे ताकि माटी से जुड़े ग्रामीणजन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ रहें। माटी की सोंधी-सोंधी महक हमारे लोक गीतो से आती रहे और खेल परंपरा की यह अविरल धारा निरंतर गतिमान रहे।

## 1. हरेली शब्द का अर्थ और महत्व

'हरेली' शब्द 'हरियाली' से बना है। सावन के महीने में जब चारों तरफ़ खेतों और मैदानों में हरी-भरी फसलें और हरियाली लहलहाने लगती है, तब किसान इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का पहला तिहार माना जाता है, जहाँ से राज्य के प्रमुख लोक-पर्वों की श्रृंखला शुरू होती है।

## 2. कृषि उपकरणों और पशुधन की पूजा

### हरेली का दिन मुख्य रूप से कृषकों और कृषि से जुड़े साधनों का धन्यवाद ज्ञापित करने का दिन है –

- कृषि यंत्रों की पूजा - हरेली की जड़ें छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कृषि विरासत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह एक उत्सव होने के साथ-साथ एक आध्यात्मिक भेंट भी है, लोगों के लिए प्रकृति, बारिश और अपने कृषि कार्य को सम्पन्न करने के बाद किसान अपने औजार, हल, फावड़ा, कुदाल, कुदाली, कुम्हड़ी, बिन्धना, बसुला, हथौड़ी, आरी,असिया, पैसुल, छूरा, खुर्पी आदि को धोकर स्वच्छ मिट्टी (मुरमी) का आसन से सजाकर किसान-किसानिन पूजा सामग्री रखकर धुले हुए चांवल आटे से हाथा लगाकर चन्दन, फूल, धुप-दीप व चीला रोटी से भोग लगाकर

श्रीफल अर्पित करते हैं एवं भाव विभोर हो प्रार्थना करते हैं - 'हे बलराम रूपी हल प्रचण्ड शक्ति के प्रतीक धारापति, आपने कंधा के रूप में माता को संवारा एवं सेवा करने में हमारी सहायता की कृषि कार्य बोनी ब्यासी रोपा के होते ही चहूओर हरियाली छाई इसके लिए कोटिशः धन्यवाद आपका कार्य सम्पन्न हुआ विश्राम करे। हमने आपको बड़ा कष्ट दिया, काम लिया, हमें क्षमा करें। आपकी दया हम पर सदैव बनी रहे, इसी प्रकार अन्य औजारों का कार्यानुसार निवेदन करते गेड़ी की पूजा कर शरीर के सामर्थ पैरो की रक्षा की कामना करते हैं।

– **पशुधन का सत्कार** – पशुधन किसानों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें फसल और पशुधन का संयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कम पढ़े-लिखे और अकुशल होने के कारण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। बैल छत्तीसगढ़ कृषि की रीढ़ हैं। किसान, विशेषकर सीमांत और लघु किसान, जुताई, ढुलाई और उत्पादन और इनपुट दोनों के परिवहन के लिए बैलों पर निर्भर रहते हैं।

– **खेती-किसानी के सच्चे** – साथी यानी गाय और बैलों की विशेष सेवा की जाती है। उन्हें नहला-धुलाकर आरती उतारी जाती है तथा 'गहूंता' (आटा, नमक और जड़ी-बूटी से बना पौष्टिक मिश्रण) खिलाया जाता है, ताकि वे रोगों से मुक्त रहें। जड़ी बुटियों से तैयार औषधि को गौठान में ले जाकर अन्डी एवं खम्हार के पत्तों में नमक, चावल या गेहूँ के गोला के साथ दवा डाल कर पशुओं को खिलाया जाता है। अरण्ड, खम्हार का पत्ता औषधि है, जो वायुजनित रोगों को दूर करता है। नमक उत्प्रेक्षण का कार्य करता है, चावल या गेहूँ के कारण दवा अधिक असरकारक बन जाती है। इससे पशु धन निरोग हो जाता है यह एक प्रकार टीकाकरण ही है।

## 3. परंपराएं एवं रीति-रिवाज

- गेड़ी चढ़ने का आनंद - इस पर्व में गेंड़ी का काफी महत्व है बांस के मोटे डंडो एवं बांस के पहुये को विशेष विधि से कस कर बांधा जाता है। गेड़ी का उदारण हमें पुराणों में मिलता है। बलदाऊ-कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेड़ी चढ़ा करते थे। कृष्ण लीला प्रसंग में इसका उदाहरण मिलता है तथा खेलों का आयोजन भी होते रहे हैं, जिसमें गेड़ी दौड़, पानी पिलाना, एक पैर में खड़े होना, एक पैर में कूदना आदि अनेक खेल का आयोजन प्राचीन काल से अब तक होते आ रहे हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर चलने के साधन के रूप में शुरू हुई यह परंपरा आज एक मनोरंजक खेल बन चुकी है।

– **विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन** – हरेली में गाँव व शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होती है। सुबह पूजा-अर्चना के बाद गाँव के चौक-चौराहों पर युवाओं की टोली जुटती है और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन की जाती है। नारियल हारने और जीतने का यह सिलसिला देर रात तक चलता है। गाँव-गाँव में गेड़ी दौड़ का आयोजन होता है। कहीं खो-खो तो कहीं फुगड़ी, कहीं बिल्लस, कहीं अत्ती-पत्ती, डंडा पचरंगा खेल का आयोजन होते आ रहे हैं। गाँव का गौठान हो या स्कूल का मैदान, गाँव के बाहर सड़क हो या चौबट्टा लगता है सारे लोग रंग-बिरंगे परिधानों में सजे रहते हैं।

– **टोटका और सुरक्षा का विधान** – मान्यतानुसार, इस दिन गाँव को बुरी नज़र और रोगों से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजों पर नीम की पत्तियाँ बांधी जाती हैं। लोहार द्वारा घरों के चौखट पर नीम की शाखाएं और लोहे की कीलें लगाई जाती हैं। स्थानीय मान्यता है कि इससे घर को बुरी शक्तियों और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यह प्रथा नीम के ज्ञात औषधीय गुणों और ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक मान्यताओं में इसकी भूमिका से प्रेरित है।

– **हरेली तिहार में बनाए जाने वाले व्यंजन** – मुख्य रूप से गुड़ के चीला, अईरसा, चौसेला और बोबरा जैसे पारंपरिक पकवान बनाए और बांटे जाते हैं। गुलगुला भजिया, गुड़हा चीला, सोहारी, बड़ा, ठेठरी, खुरमी और बोबरा जैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों का भोग कृषि औजारों और गोधन को लगाया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का विशेष आनंद लिया जाता है।

## 4. सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश

हरेली तिहार केवल एक धार्मिक या लोक-अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव का प्रकृति के साथ अटूट संबंध दर्शाता है। यह पर्व सिखाता है कि जो प्रकृति और पशुधन हमें जीवन और भोजन देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है।आज के समय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर और 'छत्तीसगढ़िया क्रांति' के तहत पारंपरिक खेलों (जैसे गेड़ी दौड़) को बढ़ावा देकर इस लोक-सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

# 'सुदृढ़ कृषि व्यवस्था और पारदर्शी सुशासन से बदल रहा छत्तीसगढ़ के किसानों की तकदीर'

देश 80वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। यह अवसर केवल स्वतंत्रता के गौरव का नहीं, बल्कि विकास की उस सतत् यात्रा का भी है, जिसने भारत के कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में खेती-किसानी को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसे आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और किसान-केंद्रित बनाने का व्यापक अभियान चलाया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री  रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने, उर्वरकों की सतत् निगरानी, पारदर्शी वितरण व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर, समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है कि किसानों को समय पर प्रमाणित खाद-बीज उपलब्ध हो और किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा नकली उर्वरकों का नुकसान किसानों को न उठाना पड़े। इसी सोच के परिणामस्वरूप खरीफ 2026 में प्रदेश में 48.69 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 11 अगस्त तक 45.62 लाख हेक्टेयर अर्थात लगभग 94 प्रतिशत क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है। किसानों को अब तक 11.23 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 4.55 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। उर्वरकों के 15.55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 15.83 लाख मीट्रिक टन का भंडारण कर राज्य ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने स्वयं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुगमता से प्रमाणित खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ ही किसानों को खेती किसानी करने में किसी प्रकार की समस्या न हो, इस उद्देश्य से ठोस रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में तरल नैनो उर्वरक के प्रति किसानों को जागरूक करने का काम भी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।  कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के नेतृत्व में विभाग ने नकली एवं अमानक उर्वरकों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में प्रवर्तन कार्रवाइयों में 11.20 गुना वृद्धि दर्ज हुई और कुल कार्रवाई 44 से बढ़कर 493 मामलों तक पहुंच गई। न्यायालयीन प्रकरण 4 से बढ़कर 65, जब्ती की कार्रवाई 2 से बढ़कर 107, लाइसेंस निलंबन 3 से बढ़कर 106, लाइसेंस निरस्तीकरण 2 से बढ़कर 15 तथा विक्रय प्रतिबंध 33 से बढ़कर 189 मामलों तक पहुंचा। पहली बार ग्यारह एफआईआर दर्ज होना विभाग की शून्य सहिष्णुता नीति का प्रमाण है। इन कठोर कदमों ने किसानों का भरोसा मजबूत किया और कृषि आदानों की आपूर्ति व्यवस्था

को अधिक पारदर्शी बनाया।

सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रभाव केवल उर्वरकों तक सीमित नहीं है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 35,892.90 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 24.63 लाख किसानों को 23वीं किस्त के रूप में 493 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली। किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टैक, ई-केवाईसी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। कृषि को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और प्राकृतिक खेती पर विशेष बल दिया है। अब तक 7,745 किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तथा 568 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगभग 41,967 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार किया गया है। वहीं 57 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और कम लागत वाली खेती को प्रोत्साहित किया गया है। उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़कर 8.91 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। ऑयल पाम और बांस रोपण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि हाईटेक नर्सरी, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी अधोसंरचनाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं। पशुपालन में दुग्ध उत्पादन, डेयरी भुगतान व्यवस्था और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं मत्स्य उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 9.59 लाख टन तक पहुंच गया है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों में शामिल हो चुका है।

कृषि विपणन और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आई हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से प्रदेश की 21 मंडियां जुड़ चुकी हैं तथा कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 1,900 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 3,026 करोड़ रुपये की उपलब्धि प्राप्त हुई है। बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है तथा रायपुर की शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता मिलना राज्य की वैज्ञानिक कृषि व्यवस्था का प्रमाण है।

स्वतंत्रता के 79 वर्षों की इस ऐतिहासिक बेला पर छत्तीसगढ़ का कृषि परिदृश्य स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार की योजनाबद्ध

नीति, प्रभावी प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने खेती-किसानी को नई ऊर्जा प्रदान की है। गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीकों का समावेश और किसान-केंद्रित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश के कृषि विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध कृषि व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

# विकसित राज्य@2047– 'ज्ञान' के प्रकाश से संवरता युवाओं का भविष्य

राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश को एक सर्वसुविधायुक्त, समृद्ध और 'विकसित राज्य' के रूप में स्थापित करने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया गया है। किसी भी राज्य या राष्ट्र की प्रगति केवल भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके मानव संसाधन की दक्षता और बौद्धिक क्षमता पर टिके होती है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश के विकास मॉडल के केंद्र में 'GYAN' यानी (गरीब), (युवा), (अन्नदाता/किसान) और (नारी) को स्थापित किया गया है। आर्थिक और सामाजिक उन्नति के इस समूचे चक्र का मुख्य आधार हमारे युवा हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने, उन्हें उद्योगों की आधुनिक माँगों के अनुरूप ढालने और रोजगार-योग्य बनाने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत की जा चुकी है।

## उच्च शिक्षा विभाग एक 'मिशन मोड' में कर रहा है कार्य

प्रदेश में उच्च शिक्षा को मात्र औपचारिक डिग्रियों के वितरण तक सीमित न रखकर उसे गुणवत्तापूर्ण, व्यावसायिक और परिणामोन्मुख बनाने के लिए निरंतर नीतिगत पहल की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग एक 'मिशन मोड' में कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा मिशन योजना के माध्यम से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के सकल नामांकन अनुपात पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2021-22 में जहाँ प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 19.6 प्रतिशत था, वहीं विभाग के सतत प्रयासों से यह बढ़कर वर्तमान में 27.5 प्रतिशत हो चुका है। सरकार का लक्ष्य NEP-2020 के अनुरूप वर्ष 2035 तक इस अनुपात को 50 प्रतिशत तक पहुँचाना है।

## सर्वसुविधायुक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है

विद्यार्थियों के सर्वांगीण और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक र्वसुविधायुक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही, शोध और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य रिसर्च एवं इनोवेशन योजना का खाका तैयार किया गया है। शिक्षा को जड़ों से जोड़ने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली को भी विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है।

## प्रदेश के कुल 343 शासकीय महाविद्यालयों में से नैक मूल्यांकन के लिए पात्र

उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के नैक मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 343 शासकीय महाविद्यालयों में से नैक मूल्यांकन के लिए पात्र 254 महाविद्यालयों में से 200 का मूल्यांकन सफलता से पूर्ण हो चुका है। इसी तरह प्रदेश के 09 विश्वविद्यालयों में से 05 विश्वविद्यालयों का नैक मूल्यांकन संपन्न हो गया है। इससे न केवल संस्थानों की गुणवत्ता सुधर रही है, बल्कि विद्यार्थियों को भी पारदर्शी आधार पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुनने का अवसर मिल रहा है।

## प्रदेश में 08 नए शासकीय महाविद्यालय, 05 नए निजी महाविद्यालय तथा 03 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

भविष्य की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक अवसंरचना का भी तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 08 नए शासकीय महाविद्यालय, 05 नए निजी महाविद्यालय तथा 03 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। केवल भवनों का निर्माण ही नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए प्राध्यापकों के 595 पदों और सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी के 700 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे ये समन्वित प्रयास केवल व्यवस्थागत सुधार नहीं हैं, बल्कि यह हमारे युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने और वर्ष 2047 के स्वर्णिम व विकसित प्रदेश की ठोस नींव रखने की एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता है।

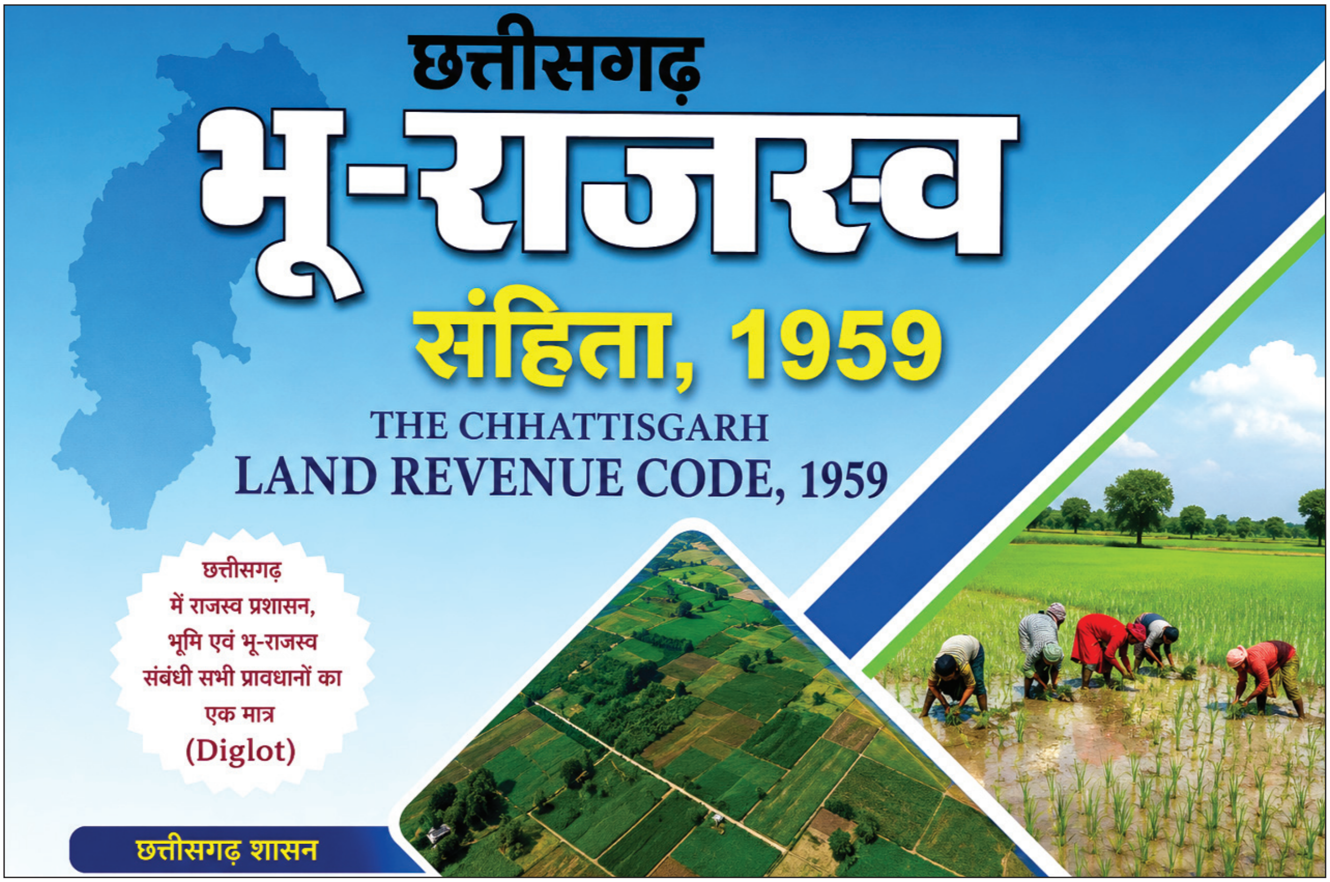


# छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार - सुशासन, डिजिटलीकरण और जन-राहत का नया

राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण और रजिस्ट्री जैसे कार्य ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए गए हैं। इसके मुख्य लाभों में ऑटो म्यूटेशन, मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड डाउनलोड और डिजिटल भुगतान शामिल हैं।

आम जनता के लिए राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा और समय लेने वाले माने जाते रहे हैं। जमीन के नामांतरण से लेकर कोर्ट के चक्कर काटने और नामांतरण-सीमांकन में होने वाली देरी से आम नागरिक अक्सर परेशान रहता था। इसी प्रशासनिक जटिलता को समाप्त कर प्रक्रिया को पारदर्शी, सुलभ और जन-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में कई युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधन किए हैं। यह सुधार न केवल आधुनिक दौर की डिजिटल जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि राज्य में सुशासन की नींव को और अधिक मजबूत करते हैं।

इन संशोधनों की सबसे बड़ी खासियत राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण है। अब धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही, धारा 30 में संशोधन करते हुए राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किया गया है।

इतना ही नहीं, भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़ी विवादित

स्थितियों से निपटने के लिए धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शों को अधिमान्यता दी गई है,

जिससे जमीन से जुड़े सटीक आंकड़े और सीमांकन पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे।

जमीनों के अनावश्यक विखंडन और भू-अर्जन के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। धारा 70 में किए गए संशोधन के अनुसार अब 05 डिसमिल से कम कृषि भूमि के बंटवारे पर रोक लगा दी गई है, ताकि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे। वहीं धारा 165, 172 और 178 में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना या आशय पत्र जारी होते ही संबंधित भूमि के अंतरण, व्यपवर्तन और खाता विभाजन पर तुरंत रोक लग जाए, जिससे किसी भी तरह के अवैध लाभ या धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।

आम जनता को सबसे बड़ी राहत जमीन के नामांतरण और पारिवारिक उत्तराधिकार के नियमों में मिली है। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के तहत अब स्वतः नामांतरण की व्यवस्था की गई है,

जिसके अंतर्गत पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार दे दिया गया है। यानी अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगी। इसके अलावा, राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध विधिक वारिसानों के पक्ष में स्वतः ई-नामांतरण का प्रावधान किया गया है। अब भूमि स्वामी को यह अधिकार भी मिल गया है कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध करा सके, जिससे भावी पीढ़ी को पारिवारिक विवादों और कोर्ट-कचहरी के चक्करों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगी।

संक्षेप में कहें तो, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए ये संशोधन केवल नियमों का बदलाव भर नहीं हैं, बल्कि यह आम जनता के समय, धन और मानसिक तनाव को बचाते हुए एक पारदर्शी, तकनीक-संचालित और जन-हितैषी राजस्व व्यवस्था की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार का एक मील का पत्थर है।

# पोषण पखवाड़ा में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर

किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से मापी जाती है। छत्तीसगढ़ ने इसी सोच को आधार बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी नीतियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के पोषण, संरक्षण और भविष्य निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आईसीडीएस, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने राज्य को बाल विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है।

प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल एवं शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बच्चे सीखने के साथ आनंदमय वातावरण में विकसित हो सकें। मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं।

## कुपोषण पर प्रभावी प्रहार

छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत की कमी, वेट में 4.36 प्रतिशत की कमी, अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

दिसंबर 2023 में जहां बौनापन की दर 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह उपलब्धि पोषण प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग, सामुदायिक सहभागिता और आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

## पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन

राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह के दौरान 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़ा में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गई। साथ ही स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है।

मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हो गई है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है।

## मिशन वात्सल्य से बच्चों को सुरक्षा और संबल

अनाथ, परित्यक्त और विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य प्रभावी सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा, देखभाल और पुनर्वास का लाभ मिला है। चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त 1 लाख 65 हजार 979 कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों मामलों का निराकरण किया गया। बाल संरक्षण सेवाओं के विस्तार का प्रभाव दत्तक ग्रहण और स्पॉन्सरशिप योजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। दत्तक ग्रहण से लाभान्वित बच्चे 42 से बढ़कर 234 और स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित बच्चे 767 से बढ़कर 2 हजार 37 हो गए हैं। यह वृद्धि बच्चों को पारिवारिक वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता दोनों को नई दिशा दी है। बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारियों की संख्या बढ़कर 1 हजार 382 हो गई है।

इसके परिणामस्वरूप रोके गए बाल विवाहों की संख्या 109 से बढ़कर 888 तक पहुंच गई है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का संकेत है।

## भविष्य की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित ये प्रयास छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षा, शिक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

आधुनिक आंगनबाड़ी व्यवस्था, पोषण सुधार, बाल संरक्षण सेवाओं का विस्तार और बाल विवाह उन्मूलन जैसे बहुआयामी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को बाल विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी और आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है।

सशक्त बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है और राज्य सरकार उसी नींव को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

# जीवंत हो उठा छत्तीसगढ़ के अनगिनत वीर जनजातीय पुरखों का अमर स्वाभिमान

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर केवल स्वतंत्रता का एक वार्षिक पर्व नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के तर्पण का दिन है जिन्होंने अपनी देह को भारत माता के चरणों में समर्पित कर आज़ादी के वटवृक्ष को सींचा था। जब संपूर्ण देश लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहरते देख गर्व महसूस कर रहा होता है, तब छत्तीसगढ़ की पावन धरा नवा रायपुर अटल नगर में सीना ताने खड़ा 'शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय' देश के इतिहास में दर्ज उन स्वर्णिम पन्नों की याद दिलाता है जो लंबे समय तक उपेक्षित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्योत्सव की रजत जयंती के पावन अवसर पर 01 नवंबर 2025 को राष्ट्र को समर्पित यह भव्य संग्रहालय केवल पत्थरों और माटी का ढांचा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की माटी के उन अमर नायकों का जीवंत स्पंदन है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के क्रूर तंत्र के आगे कभी सिर नहीं झुकाया।

छत्तीसगढ़ का इतिहास सदैव से संघर्ष, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा का इतिहास रहा है। 1857 की महान क्रांति में सोनाखान की माटी से क्रांति का शंखनाद करने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान आज भी जन-जन के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जलाता है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह संग्रहालय प्रदेश का पहला ऐसा स्मारक है जो विशेष रूप से जनजातीय नायकों के शौर्य को समर्पित है। जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थापित यह संग्रहालय 14 से 16 भव्य गैलरियों में विभाजित है, जहाँ लगभग 650 से अधिक अत्यंत सुंदर और जीवंत मूर्तिशिल्प स्थापित किए गए हैं। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ 18वीं और 19वीं शताब्दी के उन ऐतिहासिक जनजातीय विद्रोहों को दर्शाया गया है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। दर्शक यहाँ हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह,

रहे हैं। महज दस महीनों के भीतर 2.50 लाख से अधिक लोग इसका अवलोकन कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैरीकॉम सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, सेना के जवान और विदेशी पर्यटकों का दल यहाँ आकर छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा की सराहना कर चुका है। स्थानीय लोगों के लिए यह संग्रहालय रोजगार के नए अवसर भी लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के सतत मार्गदर्शन तथा प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के प्रशासनिक नेतृत्व में बना यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता रहेगा कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। छत्तीसगढ़ के इन अमर सेनानियों का बलिदान हमें सदैव अपने राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा करने की प्रेरणा देता रहेगा।

परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह और सोनाखान विद्रोह की शौर्यगाथाओं को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह के लिए दो अलग-अलग विशेष गैलरियाँ बनाई गई हैं।

यह संग्रहालय केवल प्राचीन गाथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक तकनीक और गहन शोध का एक बेजोड़ उदाहरण है। इतिहास की घटनाओं को व्हीएफएक्स टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन वर्क और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऐसा रूप दिया गया है कि आगंतुक इतिहास को केवल देखते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं। प्रत्येक दीर्घा में डिजिटल बोर्ड लगे हैं, जहाँ आगंतुक अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके या मॉनिटर और माइक्रोफोन के माध्यम से संबंधित विद्रोह की संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आगंतुकों का मार्गदर्शन करने के लिए गाइड्स की व्यवस्था की गई है। संग्रहालय में पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल, पार्किंग, सीसीटीवी सुरक्षा, प्राथमिक उपचार केंद्र और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं के साथ-साथ शिशुवती महिलाओं के लिए विशेष शिशु देख-रेख कक्ष की भी उत्तम व्यवस्था की गई है।

उद्घाटन के बाद से ही यह संग्रहालय देश-विदेश के पर्यटकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। छुट्टियों के दिनों में यहाँ प्रतिदिन चार से पाँच हजार और आम दिनों में एक से दो हजार दर्शक पहुँच

# नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर – मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस माँ भारती की वंदना, हमारे गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का पावन अवसर है। मुख्यमंत्री साय ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर सहित स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अलख जगाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर और आयतु माहरा सहित जननायकों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश - 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं', संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी का 'मनखे-मनखे एक समान' का उद्घोष हमें स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों की निरंतर प्रेरणा देता है। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए उनके राष्ट्रीय एकता के संकल्प का स्मरण किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन बदलते बस्तर की नई पहचान का प्रतीक है। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्तर मुन्ने अभियान' के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करते हुए बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।

'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' में 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की 'आजीविका उन्नयन योजना' तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं तथा वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू 'सेवा डेरा' के माध्यम से नागरिक सुविधाओं, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सड़क, बिजली, परिवहन और संचार की मजबूत बुनियाद तैयार की जा रही है।

सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित बिजली प्रणाली से जोड़ने तथा 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा' से बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं और उनका सुख, सम्मान तथा समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जा रहा है। 'कृषक उन्नति योजना' की राशि का एकमुश्त भुगतान होली से पहले किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसल लेने पर 'कृषक उन्नति योजना' के अंतर्गत 15 हजार रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश के 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया है और इनमें से 1,988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की सोच को आगे बढ़ाते हुए 'सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना' के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। अटल सिंचाई योजना के माध्यम से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इंद्रावती नदी पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिनसे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें साढ़े पांच हजार रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जा रहा है तथा 'चरण पादुका योजना' पुनः प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मोदी की गारंटी' के अनुरूप प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति के बाद अब तक 24 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'महतारी वंदन योजना' के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। योजना के अंतर्गत अब तक 19 हजार 444 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए हैं। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं, वहीं 6,691 जनजातीय बहुल गांवों में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का लाभ दिया जा रहा है। वनाधिकार पत्र वितरण में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वारिसों के पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। मुख्यमंत्री साय ने स्वामी विवेकानंद के युवा शक्ति पर विश्वास का स्मरण करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल, खेल और नवाचार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल' बनाया गया है तथा परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया गया है।

# विभाजनकारी ताकतों से रहें सतर्क, इतिहास से सबक लेकर राष्ट्र की एकता को करें मजबूत - अरुण साव

**उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्य  म में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में देश की एकता और अखंडता के लिए सभी से सजग रहने का आह्वान किया।**
**उन्होंने कहा कि आज भी भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें होती हैं। ऐसी ताकतों से देशवासियों को सावधान रहना होगा। साव ने कहा कि 14 अगस्त 1947 का विभाजन केवल जमीन का बंटवारा नहीं था।**

यह करोड़ों दिलों, सपनों और रिश्तों के बिखरने की दर्दनाक घटना थी। विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। अनेक लोगों ने अपने माता-पिता, भाई-बहन और प्रियजनों को खोया। लाखों परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा।

उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। विभाजन ने उस संघर्ष को गहरा दर्द दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, उसे भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

दुर्ग नगर निगम सभागार में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में  साव ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दर्द को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य इतिहास को याद रखना और भविष्य में देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना है। हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को हर परिस्थिति में मजबूत रखना है। राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा विधायक  ललित चंद्राकर, महापौर  अलका बघमार, जिला पंचायत की अध्यक्ष  सरस्वती बंजारे, पूर्व मंत्री  रमशीला साहू, सुरेंद्र कौशिक,  जितेंद्र वर्मा और  दिलीप साहू सहित अनेक प्रबुद्ध जन एवं विद्यार्थी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

# अपनी माटी और खेती-किसानी से
## मुख्यमंत्री साय का आत्मीय जुड़ाव

मुख्यमंत्री साय का अपनी माटी और खेती-किसानी से गहरा जुड़ाव आज एक बार फिर देखने को मिला। मुख्यमंत्री साय सुबह जशपुर जिले के अपने गृहग्राम बगिया में खेत पहुंचे और पारंपरिक रूप से बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाकर बियासी की। खेत में उतरकर हल की मूठ थामे मुख्यमंत्री साय सहज ही एक किसान की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने खेती-किसानी से जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी साझा किया।

मुख्यमंत्री साय ने हरे-भरे खेत में मिट्टी की सौंधी सुगंध और बैलों के साथ खेती करते हुए कहा कि अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है। हल की मूठ थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठती हैं। खेतों के बीच बिताया समय मन को असीम सुकून देने के साथ नई ऊर्जा से भर देता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और बचपन से खेती-किसानी को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया है।

खेती उनके लिए केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार है। गांव और खेतों ने ही उन्हें श्रम का सम्मान करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाया है।

**हल की मूठ थामते ही जीवंत हुई खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां**

**मुख्यमंत्री ने कहा - किसान परिवार से होने के नाते खेती मेरे लिए केवल**

**छत्तीसगढ़ की माटी, कृषि परंपरा और मेहनतकश अन्नदाता किसान सदैव हृदय के सबसे करीब- मुख्यमंत्री साय**

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की माटी, मेहनतकश किसानों और समृद्ध कृषि परंपराओं से जुड़ी हुई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में खेती का महत्वपूर्ण स्थान है।

पीढ़ियों से हमारे किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचते हुए प्रदेश की समृद्धि की नींव मजबूत करते आए हैं। छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार, परंपराएं और ग्रामीण जीवन भी कृषि से गहराई से जुड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खेती हमें परिश्रम, धैर्य और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देती है। किसान खेत में केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि अपने श्रम से पूरे समाज के जीवन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी, हमारी समृद्ध कृषि परंपरा और हमारे मेहनतकश अन्नदाता किसान सदैव उनके हृदय के सबसे करीब हैं। किसानों की खुशहाली और कृषि की समृद्धि ही प्रदेश की समृद्धि का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के परिश्रम को नमन करते हुए उनके जीवन में खुशहाली तथा खेतों में भरपूर फसल की कामना की।

## 'खेती से मुख्यमंत्री का रहा है पुराना नाता'

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जीवन ग्रामीण परिवेश और खेती-किसानी से गहराई से जुड़ा रहा है। सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने गांव, खेत और ग्रामीण परिवेश से जुड़कर आत्मीयता का अनुभव करते हैं। आज सुबह गृहग्राम बगिया के खेत में बैलों के साथ हल चलाते मुख्यमंत्री की सहजता में अपनी माटी और कृषि परंपरा के प्रति उनका यही गहरा लगाव दिखाई दिया।

# डिजिटल क्रांति से सुदृढ़ होता राजस्व प्रशासन-सुशासन और पारदर्शिता की नई सुबह

सुशासन की दिशा में अग्रसर राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन को डिजिटल बनाकर आम जनता के जीवन को सरल और चिंतामुक्त करने का एक ऐतिहासिक अध्याय शुरू किया है। वह दौर अब बीते दिनों की बात हो चुका है, जब जमीन-जायदाद के कागजात दुरुस्त कराने, नामांतरण कराने या खसरा-नक्शा हासिल करने के लिए नागरिकों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज आधुनिक तकनीक के समन्वय से राजस्व सेवाएं न केवल पारदर्शी हुई हैं, बल्कि सीधे नागरिकों की पहुंच में आ चुकी हैं।

## 19 हजार 723 गांवों के भू - नक्शों का पूर्णतः कंप्यूटरीकृत

छत्तीसगढ़ में भुईयां और भू-नक्शा डिजिटल पहल के तहत प्रदेश के 20 हजार 298 गांवों के खसरा एवं 19 हजार 723 गांवों के भू-नक्शों का पूर्णतः कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है। इससे शुद्ध और प्रामाणिक भू-अभिलेख तुरंत उपलब्ध हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की स्वीकृत 172 तहसीलों में से 158 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण पूरा हो चुका है। भू-अभिलेखों के डिजिटल सुरक्षित संधारण से अभिलेखों के फटने, खराब होने या गुम होने की पुरानी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई है।

## पक्षकारों के मोबाइल पर एसएमएसके माध्यम से सुनवाई की तारीख

न्यायिक प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट व्यवस्था लागू की गई है। इसके माध्यम से नागरिक अब घर बैठे भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर अंतिम फैसले तक की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। यही नहीं, पेशी की अगली तारीख की सूचना भी पक्षकारों को सीधे उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेज दी जाती है।

## वर्ष 2025 से लागू की गई 'ऑटो नामांतरण' व्यवस्था

प्रशासनिक सुगमता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण पंजीयन और नामांतरण प्रणाली का एकीकरण है। राज्य के सभी 105 उप-पंजीयक कार्यालय अब भुईयां पोर्टल से सीधे जुड़ चुके हैं। वर्ष 2025 से लागू की गई 'ऑटो नामांतरण' व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री होते ही क्रेता के नाम पर नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। एनआईसी द्वारा विकसित इस प्रणाली से ऑफलाइन नामांतरण में लगने वाले समय और अनावश्यक परेशानियों से नागरिकों को स्थायी राहत मिल रही है।

## गाइडलाइन दर का निर्धारण स्वचालित प्रणाली से

भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी 'ऑटो व्यपवर्तन' के जरिए बेहद सरल बनाया गया है, जहाँ आवेदन मिलने के मात्र 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। गाइडलाइन दरों और प्रीमियम दरों का निर्धारण भी अब स्वचालित प्रणाली से संपन्न होता है।

## डिजिटल किसान पुस्तिका उपलब्ध

किसानों के हित में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भुईयां पोर्टल पर डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है। पटवारी और उप-पंजीयक के डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त यह प्रमाणित दस्तावेज़ सिस्टम द्वारा स्वतः तैयार हो जाता है। आगामी समय में इसे सिविल न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे भूमि से जुड़े किसी भी अदालती स्थगन या आदेश की अद्यतन जानकारी इसमें पारदर्शी रूप से दर्ज रहेगी।

## खसरा व बी-1 की डिजिटल सुलभता

डिजिटल सुलभता की इस कड़ी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए खसरा व बी-1 जैसे सभी मुख्य दस्तावेज़ अब व्हाट्सएप चैटबॉट पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, तकनीक आधारित इस राजस्व क्रांति ने न केवल समय और धन की बचत की है, बल्कि प्रदेश में सुशासन, प्रामाणिकता और पारदर्शिता की एक नई मिसाल पेश की है।

# सुपरफूड मखाना

## को खाने के 5 हेल्दी तरीके, नोट करें आसान रेसिपी

आजकल स्वस्थ खानपान अपनाने वाले लोगों के बीच मखाना तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसे हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला फूड माना जाता है. मखाने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

यही वजह है कि इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाने की सलाह दी जाती है. कम कैलोरी और कम फैट होने के कारण यह हेल्दी स्नैक के रूप में भी पसंद किया जाता है.

संतुलित मात्रा में मखाने का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद कर सकता है. यह हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है.

अच्छी बात यह है कि मखाने को कई स्वादिष्ट और हेल्दी तरीकों से तैयार किया जा सकता है, जिससे स्वाद और पोषण दोनों का लाभ मिलता है. आइए जानते हैं कि मखाने से कौन-कौन सी आसान रेसिपी बनाई जा सकती हैं, इसे और पौष्टिक कैसे बनाया जा सकता है और इसे खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

### मखाने से बनाएं ये 5 हेल्दी और टेस्टी रेसिपी

#### रोस्टेड मखाना

मखानों को एक पैन में थोड़ा घी या ऑलिव ऑयल डालकर हल्का भून लें. इसमें काली मिर्च, हल्दी, चाट मसाला या थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं. यह जल्दी बनने वाला हेल्दी स्नैक है. इसमें फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकते हैं.

#### मखाना चाट

भुने हुए मखानों में टमाटर, प्याज, खीरा, हरा धनिया, नींबू का रस और हल्का चाट मसाला मिलाकर चाट तैयार करें. चाहें तो इसमें उबला चना भी मिला सकते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हल्का स्नैक बन जाता है.

#### मखाना रायता

मखानों को हल्का भूनकर छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. इन्हें फेंटे हुए दही में मिलाएं और ऊपर से भुना जीरा, काला नमक तथा हरा धनिया डालें. यह ठंडक देने वाला पौष्टिक व्यंजन है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक का अच्छा मेल मिलता है.

#### मखाना भेल

भुने हुए मखानों में खीरा, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, भुना चना और नींबू का रस मिलाकर भेल तैयार करें. स्वाद के लिए थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं. यह कम कैलोरी वाला हेल्दी स्नैक है, जो फाइबर और विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता

है.

## मखाना खीर

दूध को उबालें और उसमें हल्के भुने हुए मखाने डालकर धीमी आंच पर पकाएं. स्वाद के लिए इलायची, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और सीमित मात्रा में गुड़ या खजूर का पेस्ट मिला सकते हैं. यह पौष्टिक मिठाई है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

## मखाने के साथ कौन-सी चीजें मिलाकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है?

मखाने के साथ दूध, दही, बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स, अलसी के बीज और ताजे फल मिलाए जा सकते हैं. नमकीन रेसिपी में हरी सब्जियां, उबला चना या अंकुरित दालें भी शामिल की जा सकती हैं.इससे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है. इस तरह मखाना और भी संतुलित तथा पौष्टिक भोजन का हिस्सा बन सकता है.

## मखाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मखाने का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करें. ज्यादा घी, मक्खन, नमक या मीठा मिलाने से इसकी पौष्टिकता कम हो सकती है. ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले मखाने चुनें. अगर वजन कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो इन्हें हल्का भूनकर या कम तेल में तैयार करें. किसी विशेष बीमारी या डाइट प्लान का पालन कर रहे हैं, तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

# रोनाल्डो के संन्यास की खबर से फुटबॉल जगत में भूचाल, क्या 2026 बनेगा CR7 के सफर का आखिरी पड़ाव?

दुनिया के उत्तम फुटबॉलरों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करोड़ों प्रशंसकों को एक बड़ा झटका दिया है। 25 वर्षों तक फुटबॉल के मैदान पर राज करने के बाद, पुर्तगाल के इस स्टार खिलाड़ी ने संकेत दिया है कि उनका करियर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। रोनाल्डो ने हाल ही में स्वीकार किया है कि मौजूदा सत्र संभवतः खेल में उनका आखिरी साल हो सकता है। इस खबर ने न केवल उनके फैंस को भावुक कर दिया है, बल्कि खेल जगत में एक नई बहस छेड़ दी है।

## वोग को दिए इंटरव्यू में छलका रोनाल्डो का दर्द

41 वर्षीय रोनाल्डो वर्तमान में सऊदी प्रो लीग के क्लब अल-नस्र के साथ जुड़े हुए हैं, जहां उनका करार जून 2027 तक है। हालांकि, करार की अवधि लंबी होने के बावजूद रोनाल्डो ने संन्यास की ओर इशारा कर दिया है। 'वोग' पत्रिका को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह शायद फुटबॉल में मेरा आखिरी साल है। मैं एक शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं।

रोनाल्डो की यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपने संन्यास के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की थी। हालांकि, उन्होंने पिछले साल नवंबर में उम्मीद जताई थी कि वे 'एक या दो साल' और खेलेंगे और साल 2026 में अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे।

## 25 साल का सफर और अनगिनत त्याग

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पांच बार 'बैलोन डी'ओर' जीतने वाले इस खिलाड़ी ने खेल के प्रति अपने समर्पण को लेकर कहा कि उनका 25 साल का सफर बहुत सारे त्यागों से भरा रहा है। रोनाल्डो ने जोर देकर कहा कि वह मैदान से हटते समय एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। मैदान पर उनकी गति और गोल करने की कला ने उन्हें 'GOAT'

की श्रेणी में ला खड़ा किया है। स्पेन के खिलाफ पिछले महीने 'राउंड ऑफ 16' में मिली हार के बाद पुर्तगाल का सफर समाप्त होने से रोनाल्डो को गहरा धक्का लगा था, जिसने शायद उन्हें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया।

## फुटबॉल के बाद की जिंदगी

रोनाल्डो ने केवल संन्यास का संकेत ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खेल के बाद की अपनी जिंदगी के लिए पूरी योजना भी बना ली है। दिलचस्प बात यह है कि 11 अगस्त 2026 को रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिग्ज से शादी की थी। निजी जीवन में आए इस बड़े बदलाव के बाद अब वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक हैं।

अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, फुटबॉल एक बड़ी खाली जगह छोड़ सकता है, इसलिए आपको अपना समय अलग-अलग तरीकों से भरना होता है÷। वह अब ज्यादा घूमने-फिरने, पैडल खेलने और अपनी मेहनत से कमाई गई खुशियों का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं।

## क्या वर्ल्ड कप 2026 में दिखेगा आखिरी जादू?

फैंस के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोनाल्डो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? पहले उन्होंने इस वर्ल्ड कप को अपना आखिरी टूर्नामेंट बताया था, लेकिन उनकी हालिया बातों से लगता है कि वह शायद उससे पहले ही खेल को अलविदा कह सकते हैं।

रोनाल्डो का रिटायर होना एक युग का अंत होगा। फिलहाल, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी यह दुआ कर रहे हैं कि वे अपने करियर के इस आखिरी साल में रोनाल्डो के पैरों का वही पुराना जादू एक बार फिर देख सकें।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जाना फुटबॉल के मैदान पर एक ऐसा शून्य पैदा करेगा जिसे भरना नामुमकिन होगा। क्या वे अपनी विरासत को एक और बड़े खिताब के साथ खत्म करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा।

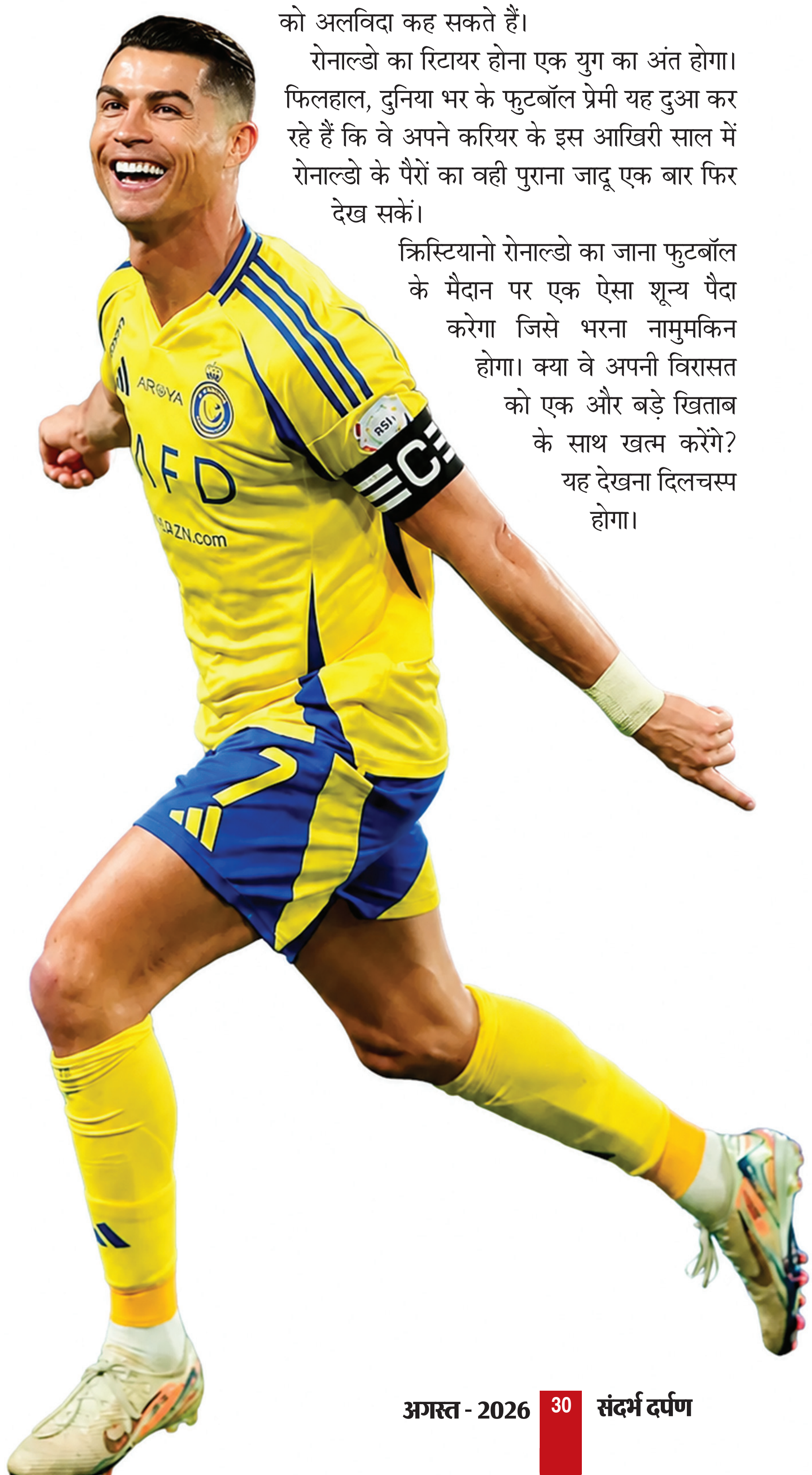

रिलीज़ के आठ साल बाद भी, गीता गोविंदम दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है, इसका क्रेडिट पैन-इंडियन स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के बीच यादगार केमिस्ट्री को जाता है। उनकी पहली फिल्म साथ में तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें रश्मिका की चार्मिंग गीता और विजय के प्यारे गोविंद ने कई पीढ़ियों के दर्शकों का दिल जीता। उनकी आसान दोस्ती और नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया। गीता गोविंदम के आठ शानदार साल पूरे होने पर, आइए जानते हैं कि उनकी जादुई केमिस्ट्री क्यों यादगार बनी हुई है।

## 1. एक ऐसी केमिस्ट्री जो आसानी से असली लगी

रश्मिका और विजय के नैचुरल कम्फर्ट ने गीता और गोविंद के रोमांस को असली बना दिया। उनकी मज़ेदार नोकझोंक, इमोशनल पल और अजनबियों से सोलमेट बनने का भरोसेमंद सफ़र दर्शकों को बांधे रखता है और इस जोड़ी को तुरंत रिलेट करने लायक बनाता है।

## 2. रोमांस, कॉमेडी और इमोशन का परफेक्ट मिक्स

मज़ेदार गलतफहमियों से लेकर दिल को छू लेने वाले सीन तक, इस जोड़ी ने रोमांस, कॉमेडी और इमोशन को आसानी से बैलेंस किया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक नया चार्म दिया और हर बातचीत को यादगार बना दिया।

## 3. छोटे-छोटे पल जिन्होंने बड़ा असर डाला

उनकी हल्की मुस्कान, मतलब भरी नज़रें और एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस अक्सर डायलॉग से परे इमोशन दिखाती हैं। रश्मिका और विजय हर सीन में गहराई और सच्चाई लाए, जिससे उनका रोमांस असली लगा।

### 4. गाने जिन्होंने उनके ऑन-स्क्रीन जादू को और बढ़ाया

इनकेम इनकेम इनकेम कावाले, येंटी येंटी, और वचिंडम्मा जैसे गानों ने उनकी केमिस्ट्री को खूबसूरती से दिखाया। उनकी आसान स्क्रीन प्रेजेंस और ज़बरदस्त एनर्जी ने हर ट्रैक को फैंस का पसंदीदा बना दिया जिसे आज भी पसंद किया जाता है।

### 5. एक ऐसी जोड़ी जिसे दर्शक आज भी दोबारा देखना चाहते हैं

आठ साल बाद भी, रश्मिका और विजय तेलुगु सिनेमा के सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन कपल्स में से एक हैं। फैंस गीता गोविंदम का जश्न मना रहे हैं और उन्हें किसी और फिल्म में फिर से साथ देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

### 6. 'येंटी येंटी' वॉक जो तुरंत आइकॉनिक बन गई

येंटी येंटी के दौरान उनका स्टाइलिश वॉक फिल्म के खास पलों में से एक बन गया। उनके आसान सिंक, मज़ेदार एक्सप्रेशन और ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने इस सीन को आइकॉनिक बना दिया, जिससे अनगिनत फैंस ने इसे दोबारा बनाया।

## 7. फ़ूड प्लेट एक्सचेंज सीन जिसने सबका दिल जीत लिया

अब मशहूर हो चुके फ़ूड प्लेट एक्सचेंज ने गीता और गोविंद के बढ़ते रिश्ते को पूरी तरह से दिखाया। आसान एक्सप्रेशन और नैचुरल परफॉर्मेंस के ज़रिए, रश्मिका और विजय ने अपनापन और अपनापन दिखाया, जिससे यह फ़िल्म के सबसे पसंदीदा सीन में से एक बन गया। गीता गोविंदम के आठ सफल साल पूरे होने पर, दोनों स्टार्स नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। रश्मिका की आने वाली लाइनअप में मायसा, राणाबली, पुष्पा 3, एनिमल पार्क और राका शामिल हैं,

जबकि विजय देवरकोंडा राणाबली, राउडी जनार्दन और VDXShoryuv में नज़र आएंगे। आज भी, दर्शक उनके साथ मिलकर बनाए गए जादू को प्यार से याद करते हैं और एक और कोलेबोरेशन की उम्मीद करते हैं।

adani

# आज़ादी के 79 साल

## संघर्ष से सम्मान तक,
## सपनों से नए भारत तक

यह उत्सव उस भारत का है
जो हर चुनौती के बाद और मज़बूत होकर उभरता है,
और हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है।

अदाणी परिवार की ओर से
**स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं**

# सरल सुगम सशक्त

**श्री नरेन्द्र मोदी**
माननीय प्रधानमंत्री

## प्रशासनिक सुधार

- सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा, ई-ऑफिस प्रणाली
- अटल डैशबोर्ड
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप
- सीएम हेल्पलाइन 1076

## राजस्व एवं पंजीयन सुधार

- प्रदेश में 119 पंजीयन कार्यालय बन रहे स्मार्ट
- भूमि विवाद रोकने जियो-रेफरेंसिंग
- 10 क्रांतियों और सुगम एप से आसान हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया
- वनाधिकार पट्टा वितरण से मिला मालिकाना हक

## ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- जन विश्वास 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल के वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित स्वीकृति
- स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2025-30 लागू
- भारत सरकार द्वारा LEADS 2025 में लैंडलॉक्ड राज्यों में हाई परफॉर्मर की मान्यता

## सेवाओं का डिजिटलीकरण

- 6,000+ पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र
- सेवा सेतु से 661 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
- अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुगम प्रक्रिया

## भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं पारदर्शिता

- जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी
- भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल के विरुद्ध कठोर कानून
- खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया हुई पारदर्शी
- लकड़ी व खनिज ब्लॉक की पारदर्शी ई-नीलामी

**श्री विष्णु देव साय**
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

## प्रशासनिक सुधार और नवाचार

प्रगति और समृद्धि का सपना हो रहा साकार